नईदुनिया

खास-खबरें

सेवा और लेन-देन कॉल के लिए ट्राई ने 1601 सीरीज लागू की

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज उपयोगिता, कूरियर और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की कंपनियों के सेवा और लेन-देन कॉल के लिए 1601 सीरीज़ नंबरों का चरणबद्ध क्रियान्वयन शुरू किया है। यह व्यवस्था बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा (बीएफएसआई) क्षेत्र तथा सरकारी संस्थाओं के लिए पहले से लागू 1600 सीरीज से अलग होगी, ताकि वित्तीय कॉल और अन्य सेवा कॉल में भ्रम न हो। ट्राई ने बताया कि बीएफएसआई क्षेत्र में 1600 सीरीज के व्यापक उपयोग से मिले अनुभव के आधार पर अब अन्य क्षेत्रों में भी भरोसेमंद नंबरिंग ढांचा लागू किया जा रहा है। पहले चरण में बिजली, पानी, गैस, एलपीजी वितरण जैसी उपयोगिता सेवाओं और कूरियर व लॉजिस्टिक्स कंपनियों को शामिल किया गया है।

निर्देश के अनुसार दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 90 दिनों के भीतर पात्र संस्थाओं का ऑनबोर्डिंग पूरा करना होगा। नंबर सीधे पात्र संस्थाओं को दिए जाएंगे, किसी मध्यस्थ या एग्रीगेटर को नहीं। इन नंबरों का उपयोग केवल सेवा और लेन-देन कॉल के लिए किया जा सकेगा, प्रचारात्मक कॉल के लिए नहीं।

एसबीआई म्यूचुअल फंड ने पेश किया बैलेंस हाइब्रिड फंड, 24 अगस्त तक निवेश का मौका

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: देश की दिग्गज एसेट मैनेजमेंट कंपनी एसबीआई म्यूचुअल फंड ने सोमवार को अपना नया फंड ऑफर 'एसबीआई बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड' लॉन्च किया। ये एक ओपन-एंडेड हाइब्रिड स्कीम है, जो निवेशकों को इक्विटी और डेट दोनों में संतुलित तरीके से पैसा लगाने का मौका देती है। कंपनी ने एक बयान में बताया कि इस स्कीम में आर्बिट्राज की अनुमति नहीं है। इसका न्यू फंड ऑफर (एनएफओ) 10 से 24 अगस्त, 2026 तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। इस स्कीम की सबसे खास बात यह है कि यह केवल इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करती है। इसमें आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। एसबीआई बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड' एक ओपन-एंडेड हाइब्रिड स्कीम है, जिसमें निवेशकों का पैसा इक्विटी और डेट दोनों में लगाया जाएगा।

डीजीएफटी ने निर्यात योजना बंद करने के लिए मैनुअल चालान जमा करने की प्रक्रिया खत्म की

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: निर्यातकों के लिए व्यापार की सुगमता बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम के तहत विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अग्रिम प्राधिकरण और निर्यात ईपीसीजी योजनाओं के अंतर्गत निर्यात दायित्व मुक्ति प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करते समय भौतिक शुल्क भुगतान के लिए चालान जमा करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने सोमवार को जारी बयान में बताया कि डीजीएफटी एक अगस्त 2026 से स्वैच्छिक सीमा शुल्क भुगतान के लिए भौतिक चालान जमा करने की अनिवार्यता समाप्त कर दिया है। सीमा शुल्क या आईसगेट से प्राप्त लाइसेंस-वार स्वैच्छिक शुल्क भुगतान डेटा को डीजीएफटी की ऑनलाइन प्रणालियों के साथ जोड़ दिया गया है।

सरकार गन्ने की जगह मक्का-चावल से एथेनॉल उत्पादन बढ़ाने पर कर रही विचार

महंगी चीनी ने बढ़ाई चिंता, एथेनॉल में गन्ने के इस्तेमाल पर लगेगी सीमा

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: देश में चीनी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के बीच केंद्र सरकार घरेलू बाजार में आपूर्ति बढ़ाने के लिए एथेनॉल उत्पादन में गन्ने के इस्तेमाल को सीमित करने पर विचार कर रही है। प्रस्तावित व्यवस्था अगले सीजन से लागू की जा सकती है। इस संबंध में अंतिम फैसला अगले महीने के अंत तक लिए जाने की संभावना है। सरकार का उद्देश्य चीनी की उपलब्धता बढ़ाकर कीमतों को नियंत्रित करना है।

मामले से जुड़े सरकारी और उद्योग सूत्रों के अनुसार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में इस वर्ष कम बारिश हुई है। दोनों राज्य देश के प्रमुख गन्ना उत्पादक हैं। कम बारिश के कारण अगले वर्ष गन्ने और चीनी के उत्पादन में कमी आने की आशंका है। ऐसे में एथेनॉल उत्पादन के बजाय चीनी की आपूर्ति को प्राथमिकता देने से घरेलू बाजार में उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है।

इस वर्ष चीनी मिलों ने कुल उत्पादन का करीब 10 प्रतिशत, यानी लगभग 30 लाख मीट्रिक टन चीनी एथेनॉल उत्पादन के लिए डायवर्ट की थी। यदि अगले सीजन में गन्ने के इस डायवर्जन को सीमित किया जाता है तो इतनी ही मात्रा में अतिरिक्त चीनी घरेलू बाजार में उपलब्ध हो सकती है। इससे कम उत्पादन के कारण होने वाली संभावित कमी की भरपाई करने में मदद मिलेगी।

भारतीय बाजार में पिछले एक महीने के दौरान चीनी की कीमतों में करीब 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। त्योहारों के सीजन में मांग बढ़ने की संभावना है। ऐसे में अगले तीन महीनों तक चीनी के दाम ऊंचे स्तर पर बने रहने की आशंका जताई जा रही है।

सरकार अपने 20 प्रतिशत एथेनॉल ब्लेंडिंग लक्ष्य को जारी रखना चाहती है। गन्ने से बनने वाले एथेनॉल में संभावित कमी की भरपाई के लिए मक्का और चावल से एथेनॉल उत्पादन बढ़ाने की योजना है। देश में मक्का और चावल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध होने की बात कही गई है।

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत चीनी मिलों को गन्ने के जूस और बी-हेवी मोलासेस से एथेनॉल बनाने की अनुमति नहीं देने पर विचार किया जा रहा है। मिलों को मुख्य रूप से सी-हेवी मोलासेस से एथेनॉल उत्पादन की अनुमति मिल सकती है। बी-हेवी मोलासेस में चीनी की मात्रा अधिक होती है, जबकि सी-हेवी मोलासेस वह गाढ़ा शीरा है, जिसमें अधिकांश चीनी पहले ही निकाल ली जाती है।

नवंबर से शुरू होने वाले नए मार्केटिंग वर्ष के लिए एथेनॉल का एलोकेशन सीजन शुरू होने से पहले तय किया जाएगा। इसके बाद सरकारी तेल कंपनियां एथेनॉल खरीद के लिए टेंडर जारी करेंगी। सरकार पहले ही चीनी निर्यात पर प्रतिबंध और व्यापारियों के लिए स्टॉक सीमा लागू कर चुकी है। उद्योग अधिकारियों के अनुसार, प्रस्तावित बदलाव से चीनी मिलों को बड़ा आर्थिक नुकसान होने की संभावना नहीं है, क्योंकि एथेनॉल की तुलना में चीनी बेचने से अधिक कमाई हो सकती है।

सेंसेक्स 43 अंक चढ़कर 78,542 पर बंद, निफ्टी में भी मामूली बढ़त

नईदुनिया ब्यूरो, मुंबई: घरेलू शेयर बाजार में सोमवार को मामूली तेजी रही। सेंसेक्स 43 अंक चढ़कर 78,542 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 13 अंक की बढ़त दर्ज की गई और यह 24,584 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान रियल्टी और निजी बैंकों के शेयरों में खरीदारी का रुझान अधिक रहा।

बाजार में सोमवार से मोलबायो डायग्नोस्टिक्स और धूत ट्रांसमिशन के आईपीओ भी खुल गए। मोलबायो डायग्नोस्टिक्स आईपीओ के जरिए 939.70 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है, जबकि धूत ट्रांसमिशन 3,066.89 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। दोनों आईपीओ में निवेश के लिए 12 अगस्त तक मौका रहेगा।

वैश्विक बाजारों में भी सोमवार को सकारात्मक रुख रहा। एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी 41 अंक यानी 0.65 प्रतिशत चढ़कर 6,300 पर पहुंचा। जापान का निक्केई 1,364 अंक यानी 2.08 प्रतिशत की बढ़त के साथ 66,970 पर रहा। हांगकांग का हैंगसेंग 269 अंक यानी 1.05 प्रतिशत बढ़कर 25,937 पर पहुंच गया।

इससे पहले 7 अगस्त को अमेरिकी बाजारों में भी तेजी रही थी। डाउ जोंस 152 अंक, नैस्डैक 342 अंक और एसएंडपी 500 सूचकांक 48 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए थे।

विदेशी निवेशकों की बाजार में खरीदारी भी जारी है। आंकड़ों के अनुसार, विदेशी निवेशकों ने पिछले सात दिनों में 1,966 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे हैं। वहीं, घरेलू संस्थागत निवेशकों ने इसी अवधि में 6,196 करोड़ रुपये की खरीदारी की। पिछले 30 दिनों में घरेलू संस्थागत निवेशकों की खरीदारी 31,601 करोड़ रुपये रही, जबकि विदेशी निवेशकों की शुद्ध बिक्री 7,464 करोड़ रुपये रही। इससे पहले शुक्रवार, 7 अगस्त को बाजार में गिरावट रही थी। सेंसेक्स 455 अंक टूटकर 78,499 पर और निफ्टी 65 अंक गिरकर 24,570 पर बंद हुआ था।

सोना 1,440 रुपये चढ़कर 1.51 लाख पर पहुंचा, चांदी भी 2.33 लाख

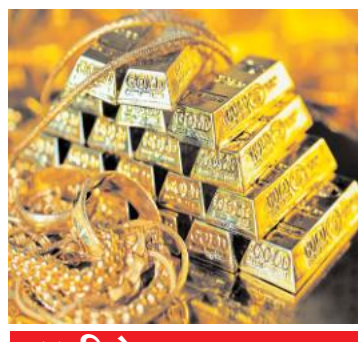

विशेषज्ञ का अनुमान- साल के अंत तक सोना 1.60 लाख और चांदी

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: सोने और चांदी की कीमतों में सोमवार को एक बार फिर तेजी दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार, 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,440 रुपये बढ़कर 1.51 लाख रुपये पर पहुंच गया। इसी तरह एक किलो चांदी की कीमत में 1,909 रुपये की बढ़ोतरी हुई और यह 2.33 लाख रुपये पर पहुंच गई। अगस्त में अब तक छह दिनों में सोना 8,201 रुपये और चांदी 14,995 रुपये महंगी हो चुकी है। इस साल सोने-चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव रहा है। 31 दिसंबर 2025 को 10 ग्राम सोने का भाव 1.33 लाख रुपये से अधिक था, जो अब बढ़कर 1.51 लाख रुपये हो गया है। इस तरह साल की शुरुआत से सोने में करीब 18 हजार रुपये की तेजी आई है। वहीं, 31 दिसंबर को एक किलो चांदी का भाव 2.30 लाख रुपये था, जो अब 2.33 लाख रुपये हो गया है। हालांकि, 29 जनवरी को सोना 1.76 लाख रुपये और चांदी 3.86 लाख रुपये प्रति किलो के ऑलटाइम हाई पर पहुंच चुकी थी। कमोडिटी विशेषज्ञ अजय केडिया के अनुसार, सोने और चांदी की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आने के बाद फिर आकर्षक दिखाई दे रही हैं। इसके चलते निवेशकों की रुचि बढ़ी है। उनका अनुमान है कि साल के अंत तक सोने की कीमत 1.60 लाख रुपये और चांदी 2.80 लाख रुपये तक पहुंच सकती है। हालांकि, उन्होंने निवेशकों को एकमुश्त निवेश से बचने की सलाह दी है।

निवेशक गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ के जरिए भी सोने-चांदी में निवेश कर सकते हैं। इनकी खरीद-बिक्री बीएसई और एनएसई पर शेयरों की तरह होती है। इसके लिए डीमैट और ट्रेडिंग खाता जरूरी है। ईटीएफ में निवेश करने पर वास्तविक सोना या चांदी नहीं मिलता, बल्कि कीमत के अनुसार राशि प्राप्त होती है।

एलपीजी ई-केवाईसी की समयसीमा नजदीक, छह दिन बाद कनेक्शन पर असर

समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर गैस कनेक्शन निलंबित होने का खतरा

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करने की समयसीमा अब करीब आ गई है। उपभोक्ताओं के पास ई-केवाईसी कराने के लिए अब केवल छह दिन शेष हैं। समयसीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के एलपीजी कनेक्शन पर असर पड़ सकता है। इंडेन, एचपी गैस और भारत गैस के उपभोक्ताओं को अपने कनेक्शन की ई-केवाईसी प्रक्रिया समय रहते पूरी करने की सलाह दी गई है।

एलपीजी कनेक्शन के लिए ई-केवाईसी का उद्देश्य उपभोक्ता की पहचान और कनेक्शन से जुड़ी जानकारी का सत्यापन करना है। इसके जरिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि एलपीजी कनेक्शन सही उपभोक्ता के नाम पर संचालित हो रहा है। ई-केवाईसी पूरी नहीं होने की स्थिति में संबंधित कनेक्शन को निलंबित किया जा सकता है और उपभोक्ता को सिलेंडर की आपूर्ति में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उपभोक्ता अपने संबंधित गैस वितरण केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा उपलब्ध डिजिटल माध्यम से भी प्रक्रिया पूरी करने की सुविधा दी गई है। उपभोक्ताओं को अपने आधार और एलपीजी कनेक्शन से जुड़ी आवश्यक जानकारी उपलब्ध रखनी होगी।

इंडेन, एचपी गैस और भारत गैस के उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया का उद्देश्य रिकॉर्ड को अपडेट रखना और कनेक्शन की जानकारी का सत्यापन करना है। जिन उपभोक्ताओं ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, उन्हें अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है।

समयसीमा समाप्त होने के बाद जिन कनेक्शनों की ई-केवाईसी पूरी नहीं होगी, उनके संबंध में गैस आपूर्ति प्रभावित होने की स्थिति बन सकती है। ऐसे में उपभोक्ताओं को अपने कनेक्शन की स्थिति की जांच कर जल्द से जल्द आवश्यक प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

ई-केवाईसी पूरी कराने से उपभोक्ता के एलपीजी कनेक्शन का सत्यापन हो जाएगा और भविष्य में सिलेंडर की आपूर्ति से संबंधित संभावित परेशानी से बचा जा सकेगा। उपभोक्ताओं को अपने संबंधित गैस वितरण केंद्र या अधिकृत डिजिटल माध्यम से प्रक्रिया की जानकारी लेकर समय रहते ई-केवाईसी पूरी करने की सलाह दी गई है।

अमेरिका में सोशल मीडिया पर सख्ती की मांग बढ़ी, 61 प्रतिशत लोग चाहते हैं निगरानी

वाशिंगटन, एजेंसी: अमेरिका में सोशल मीडिया कंपनियों पर सरकारी निगरानी और बच्चों की सुरक्षा को लेकर सख्त नियमों की मांग बढ़ रही है। रॉयटर्स-इप्सोस के एक सर्वे में 61 प्रतिशत अमेरिकियों ने कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों पर सरकार को अधिक कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। वहीं, 66 प्रतिशत लोगों ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए कंपनियों के लिए उम्र सत्यापन अनिवार्य करने का समर्थन किया।

सर्वे में 4,505 अमेरिकी लोगों को शामिल किया गया था और इसमें करीब दो प्रतिशत का मार्जिन ऑफ एरर बताया गया है। सोशल मीडिया कंपनियों पर सख्त निगरानी की मांग राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं रही। डेमोक्रेट्स के 71 प्रतिशत और रिपब्लिकन के 62 प्रतिशत लोगों ने अधिक निगरानी का समर्थन किया।

बच्चों को लेकर चिंता सर्वे में सबसे प्रमुख रही। 85 प्रतिशत अमेरिकियों ने माना कि सोशल मीडिया बच्चों के लिए एडिक्टिव हो सकता है। बड़ी संख्या में लोगों ने यह भी माना कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो सकता है। हालांकि, 70 प्रतिशत लोगों ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समय बिताना उन्हें मनोरंजक लगता है, जबकि 52 प्रतिशत ने माना कि वे इन प्लेटफॉर्म पर जरूरत से ज्यादा समय बिताते हैं।

सोशल मीडिया कंपनियों पर बढ़ते दबाव के बीच मेटा को भी अमेरिका में कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। न्यू मैक्सिको की एक अदालत ने हाल ही में मेटा को 567 मिलियन डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया है। इससे पहले इसी मामले में कंपनी पर 375 मिलियन डॉलर का जूरी अवॉर्ड लगाया गया था। दोनों को मिलाकर कंपनी की वित्तीय देनदारी करीब 942 मिलियन डॉलर हो जाती है। अदालत ने बच्चों की सुरक्षा के लिए उम्र की बेहतर जांच, नाबालिगों के इस्तेमाल पर कुछ सीमाएं, रात और स्कूल के समय सूचनाएं बंद करने तथा कुछ मामलों में अभिभावकों की अनुमति जैसे बदलावों के निर्देश दिए हैं। अमेरिका के कई राज्यों में बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर अलग-अलग नियम पहले से लागू हैं। 12 अगस्त से कैलिफोर्निया में 29 अमेरिकी राज्यों से जुड़े एक अलग संघीय मुकदमे की सुनवाई भी शुरू होने वाली है, जिसमें मेटा समेत अन्य कंपनियों पर बच्चों और किशोरों से जुड़े आरोपों की सुनवाई होगी।

स्मार्टफोन से दूरी, पुराने आईपॉड की ओर बढ़ा जेन जेड का रुझान

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: ऐपल ने 2022 में आईपॉड का उत्पादन बंद कर दिया था, लेकिन 2026 में यह पुराना म्यूजिक प्लेयर जेन जेड के बीच फिर से लोकप्रिय हो रहा है। स्मार्टफोन के बढ़ते इस्तेमाल के बीच युवा अब म्यूजिक सुनने के लिए पुराने आईपॉड का रुख कर रहे हैं। इसके पीछे डिजिटल डिटॉक्स, म्यूजिक एल्गोरिदम से दूरी और स्मार्टफोन से अलग रहने की इच्छा प्रमुख वजहें बताई जा रही हैं।

आईपॉड को खास तौर पर गाने सुनने के लिए बनाया गया था। इसमें गाने पहले से स्टोर किए जा सकते हैं और म्यूजिक सुनने के लिए इंटरनेट या सिम कार्ड की जरूरत नहीं होती। स्मार्टफोन में म्यूजिक एप्लिकेशन आने के बाद आईपॉड का इस्तेमाल कम हो गया था। अब जेन जेड के बीच इसका इस्तेमाल फिर बढ़ रहा है। जेन जेड के कई युवा डिजिटल डिटॉक्स के लिए कुछ समय स्मार्टफोन और कंप्यूटर से दूरी बनाना चाहते हैं। ऐसे में आईपॉड उन्हें बिना सोशल मीडिया और दूसरे स्मार्टफोन एप्लिकेशन के संगीत सुनने का विकल्प देता है। इससे स्क्रीन और डिजिटल गतिविधियों से दूरी बनाए रखने में मदद मिलती है। म्यूजिक एप्लिकेशन में मौजूद एल्गोरिदम भी आईपॉड की वापसी की एक वजह है। एप्लिकेशन उपयोगकर्ता की पसंद के आधार पर बार-बार उसी तरह के गाने सुझाते हैं। आईपॉड में पहले से गाने स्टोर होने के कारण ऐसा कोई एल्गोरिदम नहीं होता। उपयोगकर्ता अपनी पसंद के गाने खुद चुनता है और सुनने का पूरा नियंत्रण उसके पास रहता है।

एक स्मार्टफोन से दूसरे को ऐसे करें चार्ज, वायर्ड और वायरलेस दोनों तरीके मौजूद

रिवर्स चार्जिंग की सुविधा से फोन बन सकता है पावर बैंक, हर स्मार्टफोन में नहीं होता फीचर

बैटरी शेयर और वायरलेस पावर शेयर से बिना तार भी चार्ज कर सकते हैं स्मार्टफोन

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: स्मार्टफोन में अब बड़ी क्षमता वाली बैटरी दी जा रही है। कई फोन में 7,000 से 9,000 एमएएच तक की बैटरी उपलब्ध है। ऐसे में कुछ स्मार्टफोन जरूरत पड़ने पर दूसरे फोन को भी चार्ज कर सकते हैं। इस सुविधा को रिवर्स चार्जिंग कहा जाता है। इसके जरिए एक स्मार्टफोन अपनी बैटरी की बिजली दूसरे फोन को दे सकता है। यह सुविधा वायर्ड और वायरलेस दोनों तरीकों से उपलब्ध होती है। हालांकि, हर स्मार्टफोन में रिवर्स चार्जिंग का विकल्प नहीं मिलता।

वायरलेस तरीके से फोन चार्ज करने के लिए जिस स्मार्टफोन से बिजली दी जा रही है, उसमें रिवर्स वायरलेस चार्जिंग की सुविधा होना जरूरी है। दूसरे फोन में भी वायरलेस चार्जिंग का समर्थन होना चाहिए। कई स्मार्टफोन में इस सुविधा को बैटरी शेयर या वायरलेस पावर शेयर के नाम से दिया जाता है।

वायरलेस चार्जिंग के लिए पहले फोन की सेटिंग्स में जाकर संबंधित सुविधा चालू करनी होती है। इसके बाद दूसरे स्मार्टफोन को पहले फोन के पिछले हिस्से पर सही स्थिति में रखना होता है। दोनों फोन के चार्जिंग क्षेत्र एक-दूसरे के सामने होने चाहिए। गलत स्थिति में रखने पर चार्जिंग शुरू नहीं होगी या बहुत धीमी हो सकती है। फोन का कवर भी इसमें बाधा डाल सकता है, इसलिए जरूरत पड़ने पर उसे हटाना पड़ सकता है।

दूसरा तरीका चार्जिंग केबल के जरिए है। इसमें दोनों स्मार्टफोन को केबल से जोड़कर एक फोन से दूसरे को बिजली दी जा सकती है। हालांकि, यह सुविधा भी फोन के मॉडल और उसमें मौजूद तकनीक पर निर्भर करती है। केवल दोनों फोन में यूएसबी-सी पोर्ट होने से यह जरूरी नहीं कि एक फोन दूसरे को चार्ज कर सके।

रिवर्स चार्जिंग सामान्य चार्जर की तरह तेज नहीं होती। इसका इस्तेमाल उस समय उपयोगी है, जब आसपास चार्जर या पावर बैंक उपलब्ध न हो। इस प्रक्रिया में बिजली देने वाले फोन की बैटरी तेजी से कम होती है। वायरलेस चार्जिंग के दौरान फोन गर्म भी हो सकता है। अधिक गर्म होने पर चार्जिंग धीमी हो सकती है या फोन खुद चार्जिंग बंद कर सकता है। इसलिए रिवर्स चार्जिंग का इस्तेमाल जरूरत के समय करना बेहतर है।

प्रभाव 11 प्रमुख उत्पाद प्रभावित, डाबर ने अन्य कंपनियों के कारोबारी हित साधने का लगाया आरोप

कंपनी ने वित्तीय परिणामों के साथ नेतृत्व परिवर्तन की घोषणा की

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: एफएमसीजी कंपनी डाबर को 100 प्रतिशत दावे वाले उत्पादों के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के प्रतिबंध संबंधी आदेश पर 24 अगस्त तक रोक लगा दी है। डाबर ने एफएसएसएआई पर भेदभाव करने और प्रतिस्पर्धी कंपनियों के कारोबारी हितों को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए अदालत का रुख किया था।

डाबर ने 6 अगस्त को दायर याचिका में एफएसएसएआई की कार्रवाई को एकतरफा और बिना पर्याप्त विचार के जारी किया गया आदेश बताया। कंपनी के अनुसार, प्राधिकरण ने 100 प्रतिशत शुद्ध, 100 प्रतिशत प्राकृतिक और 100 प्रतिशत जैविक जैसे दावों वाले उत्पादों की बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी थी। साथ ही 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए थे।

डाबर का दावा है कि इस कार्रवाई से उसके करीब 150 करोड़ रुपये मूल्य के माल पर संकट खड़ा हो गया था। कंपनी के 11 प्रमुख उत्पाद प्रभावित हुए हैं। इनमें डाबर हनी, डाबर वर्जिन कोकोनट ऑयल और रियल एक्टिव कोकोनट वॉटर शामिल हैं। कंपनी का कहना है कि कुछ ऐसे उत्पाद भी प्रतिबंधित सूची में शामिल कर दिए गए, जिनके लेबल पर 100 प्रतिशत का दावा था ही नहीं।

एफएसएसएआई ने प्रोसेस्ड खाद्य उत्पादों के विज्ञापनों और लेबल पर 100 प्रतिशत शुद्ध, प्राकृतिक या जैविक जैसे दावों को भ्रामक माना है। प्राधिकरण के अनुसार, इस तरह के दावे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत बनाए गए विज्ञापन एवं दावे संबंधी नियमों का उल्लंघन करते हैं। एफएसएसएआई का तर्क है कि ऐसे दावों से उपभोक्ताओं को उत्पाद की प्रकृति को लेकर भ्रम हो सकता है।

आपूर्ति श्रृंखला पर भी असर

डाबर ने आरोप लगाया कि प्रतिबंध लगाने से पहले उसे कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया और न ही अपना पक्ष रखने या सुधार का पर्याप्त अवसर मिला। कंपनी ने कहा कि 100 प्रतिशत का दावा किसी प्रतिस्पर्धी कंपनी के उत्पाद के संदर्भ में नहीं, बल्कि स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल किया गया है और उद्योग में इसका इस्तेमाल सामान्य है।

कार्रवाई के बाद कंपनी की आपूर्ति श्रृंखला पर भी असर पड़ा। कई खुदरा और ऑनलाइन माध्यमों को प्रभावित उत्पादों की बिक्री रोकने की सलाह दी गई। कंपनी ने बताया कि वह पहले ही अपने उत्पादों के लेबल, विज्ञापनों और वेबसाइट से 100 प्रतिशत दावे हटाने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी थी। अब अदालत की 24 अगस्त तक की रोक के बाद मामले की अगली सुनवाई में एफएसएसएआई की कार्रवाई और डाबर के आरोपों पर आगे विचार होगा।